लगातार दो विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी- एम्बाप्पे

Page-04

tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

शानदार विजुअल्स से सजा रामायण का ट्रेलर

Page-05

यह सुनवाई जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली पुलिस की कथित गैर-कानूनी निगरानी से जुड़ी याचिकाओं के साथ हुई। अदालत ने निजता के अधिकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

23वें दिन भी जारी रहेगी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल

हाई कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तलब की

शिक्षा सुधार और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनका अनशन फिलहाल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनकी भूख हड़ताल अब 23वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और यह तब तक जारी रहेगी, जब तक छात्र नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने या अस्पताल में उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं मिल जाती।सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किए गए एक हस्तलिखित संदेश में वांगचुक ने कहा कि छात्रों ने पूरे आंदोलन के दौरान जिस संयम और शांति का परिचय दिया है, उससे वे भावुक और प्रेरित हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस से अपील की कि प्रदर्शनकारी छात्रों को संसद के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, ताकि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही तय करेगी।वांगचुक ने भरोसा जताया कि प्रदर्शनकारी आगे भी पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसे देशभर के छात्रों, युवा संगठनों और नागरिक समाज का समर्थन मिल रहा है।इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की पहली औपचारिक बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा है और सरकार उस पर विचार कर रही है। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की।उधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में अहम निर्देश जारी करते हुए सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल टीम और वांगचुक की ओर से नियुक्त डॉक्टरों को मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने मेडिकल जांच की वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि यदि मरीज जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसकी मेडिकल प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग किस कानूनी आधार पर की जा रही है।

- **वांगचुक ने साफ कहा कि जब तक छात्र नेताओं को संसद में सांसदों से मिलने या अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक उनका अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा।**
- **हाई कोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल और वांगचुक की मेडिकल टीम को मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तक अपनी-अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मेडिकल जांच की वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठाए।**

NEET विवाद पर केंद्र पर बरसे अखिलेश यादव, बोले- छात्रों की आवाज़ दबाना लोकतंत्र के खिलाफ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित की बजाय अहंकार के साथ काम कर रही है और छात्रों की जायज़ मांगों को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेने और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक ओर छात्रों को पुलिस थानों में रखा जा रहा है और दूसरी ओर सड़कों पर उनके साथ सख्ती की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार "सबका साथ, सबका विकास" का नारा देती है, वही छात्रों की समस्याएं सुनने को तैयार क्यों नहीं है। उनके अनुसार, यदि सरकार वास्तव में जनता की होती, तो वह युवाओं की आवाज़ को गंभीरता से सुनती।अखिलेश यादव ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दायित्व किसका था और इस मामले में अब तक जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई। उन्होंने सरकार के 'विश्वगुरु' और 'अमृत काल' जैसे नारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तब ऐसे दावों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनका कहना था कि यदि पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होते, तो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर नहीं होते। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए।

अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति

हाई कोर्ट से 30 सितंबर तक गिरफ्तारी पर राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने चुनावी भाषण मामले में उन्हें बड़ी राहत देते हुए 30 सितंबर तक पुलिस की किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी का पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अस्पताल का विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि उनका इलाज भारत में संभव नहीं है, तभी विदेश यात्रा की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने निर्धारित की गई है।सुनवाई के दौरान बनर्जी की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वह पिछले करीब दस वर्षों से अपनी आंखों का इलाज अमेरिका में कराते रहे हैं, इसलिए उन्हें उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत को बताया कि बनर्जी के विदेश जाने से उनके खिलाफ चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषण से जुड़े मामले की जांच अभी जारी है और इस दौरान उनका देश से बाहर रहना जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है।गौरतलब है कि 15 मई को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में लगाए गए आरोपों में दो गैर-जमानती धाराएं भी शामिल हैं। इसी सिलसिले में 16 जून को अपराध जांच विभाग (CID) ने उनसे करीब साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने और दो नोटिस मिलने के बावजूद वॉयस सैंपल न देने पर अभिषेक बनर्जी को फटकार लगाई थी। अदालत ने याद दिलाया था कि उन्हें पहले केवल इस शर्त पर अंतरिम राहत दी गई थी कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। बाद में कोर्ट ने उन्हें 15 जुलाई तक अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया था।

वैष्णो देवी यात्रा पर मौसम की मार

जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके बाद आधार शिविर कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नि:शुल्क लंगर और अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था शुरू कर दी है।श्राइन बोर्ड के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 23 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार प्रतिकूल मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार से भवन की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है।श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि कटरा बस अड्डे के पास स्थित निहारिका परिसर में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। यहां फंसे यात्रियों को भोजन के साथ-साथ आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल एवं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा के निर्देश पर बोर्ड ने अपने सभी संसाधन राहत कार्यों में लगा दिए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।इसके अलावा, श्राइन बोर्ड विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए मौसम और यात्रा की ताजा स्थिति से जुड़ी नियमित जानकारी और परामर्श जारी कर रहा है। बोर्ड जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर चौबीसों घंटे हालात पर नजर रखे हुए है।

राम मंदिर दान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT बनाने का दिया सुझाव

27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने पर विचार करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच किसी ऐसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए, जिसे इस तरह के संवेदनशील मामलों की जांच का अनुभव हो।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि पहले गठित SIT का दायित्व केवल प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना था। ऐसे में विस्तृत और अंतिम जांच के लिए अलग SIT का गठन अधिक उपयुक्त रहेगा।सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सच्चाई सामने लाने के उद्देश्य से SIT बनाई थी। जांच के दौरान टीम को ऐसे तथ्य मिले, जिनसे यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर अदालत ने पूछा कि मौजूदा SIT, जिसमें लखनऊ के आईजीपी और दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं, क्या पूरी जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कर पाएगी या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह किसी राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि एक संभावित आपराधिक मामले की जांच का मुद्दा है। अदालत का काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार हो।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है। इससे पहले SIT ने अदालत के निर्देश पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की थी। 13 जुलाई की पिछली सुनवाई में अदालत ने SIT से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी थी और राम मंदिर दान मामले में गहन जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया था।अब 27 जुलाई की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट जांच की दिशा और नई SIT के गठन को लेकर आगे का फैसला ले सकता है।

अभिजीत दीपके की हिरासत की खबर निकली गलत; दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

नई दिल्ली में सोमवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के संसद मार्च के दौरान उस समय भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जब सोशल मीडिया पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबरें तेजी से फैलने लगीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों का तत्काल खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि अभिजीत दीपके को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन हैं।इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दावा किया था कि अभिजीत दीपके को जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने सभी सांसदों से छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरने की अपील भी की थी। हालांकि, कुछ समय बाद दास ने अपना बयान अपडेट करते हुए स्वीकार किया कि दीपके को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल हाउस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अब भी मौजूद हैं और पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरत रही है।इसी बीच सौरव दास ने दावा किया कि उन्होंने और आशुतोष रांका ने करीब दो घंटे इंतजार करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर नड्डा ने आंतरिक स्तर पर चर्चा का भरोसा दिया। दास ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं।सूत्रों के अनुसार, संसद मार्च के दौरान कुछ

प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर की ओर बढ़ते हुए शास्त्री भवन के पास सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण आसपास के कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए, जिससे कई यात्री स्टेशन परिसर के भीतर ही फंस गए।

ब्रिटेन की सत्ता अब एंडी बर्नहम के हाथों में प्रधानमंत्री पद की संभाली जिम्मेदारी

ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहम ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर केअर स्टार्मर का स्थान लिया है।राजा चार्ल्स तृतीय ने स्टार्मर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बर्नहम को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।चार वर्षों में ब्रिटेन के पांचवें प्रधानमंत्री बने बर्नहम ने देश में स्थिर, जिम्मेदार और प्रभावी शासन देने का वादा किया है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने सोमवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण के लिए केअर स्टार्मर के इस्तीफे के कुछ ही समय बाद 56 वर्षीय बर्नहम को नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बकिंघम पैलेस के एक प्रवक्ता ने कहा, ''आज सुबह माननीय सर केअर स्टार्मर ने महाराज से मुलाकात करके प्रधानमंत्री और 'फर्स्ट लॉर्ड आफ ट्रेजरी' के पद से अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे महाराज ने स्वीकार कर लिया।' पिछले सप्ताह लेबर पार्टी के निर्विरोध नेता चुने गए बर्नहम के प्रधानमंत्री के रूप में तत्काल कामकाज शुरू करने और मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा करने की उम्मीद है। चार वर्षों में ब्रिटेन के पांचवें प्रधानमंत्री बने बर्नहम ने देश को "स्थिर और जिम्मेदार" राजनीति देने का वादा किया है। इससे पहले केअर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम संबोधन दिया और कहा, "मेरा काम पूरा हो गया है।" लेबर सांसद स्टार्मर (63) ने पिछले महीने पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मैं जिम्मेदारी एंडी बर्नहम को सौंप रहा हूं, जिन्हें मेरा पूरा समर्थन है।" स्टार्मर ने कहा, "मैं पूरे सम्मान के साथ जा रहा हूं, मुस्कराते हुए जा रहा हूं और हमने जो कुछ हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है।" जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने के बाद दो वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले स्टार्मर के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से विदा होने पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों ने कतारबद्ध होकर तालियां बजाकर उन्हें विदाई दी। बर्नहैम पिछले हफ्ते बिना किसी विरोध के लेबर पार्टी के लीडर चुने गए थे। वह पार्टी के नए लीडर बनने के लिए अकेले कैंडिडेट थे, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में 403 लेबर सांसदों में से 379 का नॉमिनेशन मिला। उम्मीद लगाई जा रही है कि वह कैबिनेट के लिए अपने चुने हुए नामों की घोषणा करके तुरंत प्रधानमंत्री के तौर पर काम शुरू कर देंगे। वह पिछले चार साल में देश के पांचवें प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने "स्टेबल और जिम्मेदार" पॉलिटिक्स लाने का वादा किया है। इससे पहले, स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना आखिरी भाषण दिया और फिर किंग से फॉर्मल तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए उनसे मिलने चले गए। कीर स्टारमर ने अपने आखिरी भाषण में कहा, "मेरा काम हो गया है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह बैटन बर्नहैम को देश की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्हें उनका पूरा सपोर्ट है। स्टारमर ने कहा, "मैं अच्छे से जा रहा हूं, मैं मुस्कान के साथ जा रहा हूं और हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है।" 63 साल के स्टारमर लेबर पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने पिछले महीने पद छोड़ने का ऐलान किया था। जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर के लिए भारी जीत हासिल करने के दो साल बाद डाउनिंग स्ट्रीट से कीर स्टार्मर के जाने पर उनके कैबिनेट के साथी और अधिकारी तालियां बजाने के लिए लाइन में खड़े थे।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के घर बेटे का जन्म

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के घर बेटे का जन्म हुआ है। दंपति ने चौथी बार बच्चे को जन्म दिया है। बेटे के दुनिया में आने के साथ ही जेडी वेंस ने एक और अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, 150 साल से ज्यादा समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि पद पर रहते हुए किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर बच्चे का जन्म हुआ है। आइए जानते हैं कि इस मौके पर दंपति ने क्या जानकारी दी है।अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर पत्नी उषा वेंस के साथ संयुक्त बयान जारी किया है और अपने बेटे के जन्म के बारे में लोगों से जानकारी शेयर की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ''हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम एलेक नील वेंस रखा गया है। उषा और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और हमारे तीनों बच्चे अपने छोटे भाई के स्वागत को लेकर बेहद उत्साहित हैं।"जेडी वेंस ने आगे कहा- "वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर और व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट के बेहतरीन मिलिट्री डॉक्टर और स्टाफ सदस्य हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं रहे हैं। उन्होंने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।" जानकारी के अनुसार, व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम का भी उनकी देखभाल और सहयोग कर रही थी जिसके लिए दंपति ने आभार जताया है। आपको बता दें कि जेडी वेंस की पत्नी उषा (उम्र 40 वर्ष) भारतीय मूल की हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है। उनका पूरा नाम उषा चिलुकुरी वेंस है। उषा और जेडी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उन्होंने साल 2014 में शादी कर ली थी।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। लोरान-डुमिलान बॉर्डर इलाके में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिससे मलबे में दबकर एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), वॉलंटियर्स और रेस्क्यू टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची एवं बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण डुमिलान इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। इस भारी तबाही के बीच, पहाड़ी से गिरे मलबे ने एक रिहायशी मकान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस और SDRF की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से सभी सात शव बरामद किए। इस घटना में कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण सुरनकोट इलाके में सुरन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पुलिस, SDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां बह गए या लापता लोगों की तलाश के लिए मिलकर अभियान चला रही हैं। स्निफर डॉग्स और बचाव नौकाओं की मदद से सुरन नदी के किनारे-किनारे तलाश जारी है। BJP नेता रविंदर रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लोरान इलाके में एक रिहायशी मकान पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया और सात लोगों की जान चली गई। वहीं, पुंछ के पूर्व DDC सदस्य रियाज बशीर नाज ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे।

रूसी राजधानी पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमलों में से एक

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस द्वारा कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के कुछ ही घंटों बाद, यूक्रेन ने मॉस्को की ओर 400 से ज़्यादा ड्रोन भेजे। यह रूसी राजधानी पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमलों में से एक था। इन हमलों से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहने का पता चलता है और मॉस्को के चार साल से ज़्यादा समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के हमले को खत्म करने के लिए किसी समझौते की उम्मीद अभी भी दूर की कौड़ी लग रही है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह सोमवार को महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे क्योंकि वह पिछले हफ़्ते सरकार में हुए फेरबदल के बाद घरेलू राजनीतिक संकट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इन बदलावों ने युद्ध लड़ने के तरीके को लेकर सेना के पुराने अधिकारियों और युवा इनोवेटर्स के बीच गहरी फूट को उजागर कर दिया है। ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन के लोगों को यह भरोसा दिलाने का दबाव है कि 35 साल के मिखाइलो फेडोरोव को रक्षा मंत्री के तौर पर विचार करने से हटाने और 60 साल के सोवियत-ट्रेंड जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की को सशस्त्र बलों का प्रमुख बनाए रखने से रूस के खिलाफ युद्ध की कोशिशों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। उनके इस फैसले के बाद फेडोरोव के समर्थन में और सिरस्की के विरोध में कई दिनों तक सड़कों पर प्रदर्शन हुए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक रूसी राजधानी की ओर 400 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन भेजे गए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ड्रोन शहर से काफी दूर ही गिरा दिए गए और 85 को मॉस्को के पास रोक लिया गया। मॉस्को के आस-पास के इलाके के प्रमुख आंद्रे वोरोब्योव ने बताया कि 10 लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतों और आम लोगों के इस्तेमाल वाली जगहों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को इलाके के डोमोडेडोवो क्षेत्र की प्रमुख येवगेनिया ख्रुस्तालेवा के अनुसार, इस हमले की वजह से मॉस्को से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित युझनी व्राता इंडस्ट्रियल पार्क में भी आग लग गई। 'एस्ट्रा' समाचार आउटलेट ने खबर दी है कि इस हमले के कारण मॉस्को से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में पोडोलस्क स्थित एक तेल डिपो में भी आग लग गई, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज में आग लग गई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ओमान के तट के पास सोमवार तड़के एक वाणिज्यिक जहाज में भीषण आग लग गई। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) केंद्र ने इस घटना की पुष्टि करते हुए चेतावनी जारी की है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और दोनों देश पूर्ण युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले महीने हुआ अंतरिम शांति समझौता पूरी तरह टूट चुका है, जिसके कारण इस महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है।अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोमवार तड़के ईरान पर लगातार नौवें दिन हवाई हमले किए। अमेरिका ने शनिवार को इराक में एक मार गिराए गए ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान अपने एक और सैनिक की मौत की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 17 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा, "यह हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए जारी रहेंगे, जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले नागरिक और वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के लिए किया जाता है।"ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों ने देश के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित एक निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 'दारखोविन' परमाणु साइट को निशाना बनाया है। उपग्रह से मिली तस्वीरों के अनुसार, इस साइट पर अभी शुरुआती काम ही चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था (IAEA) ने भी स्पष्ट किया है कि हालिया दौरे तक इस शुरुआती निर्माण स्थल पर कोई परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के महासचिव जसीम मोहम्मद अल-बुदैवी ने नागरिक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं पर हमलों के लिए ईरान पर 'युद्ध अपराध' का आरोप लगाया है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले प्रतिबंधित हैं, बशर्ते उनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा रहा हो।

संपादक की कलम से

देश में इस समय कई बड़े मुद्दे एक साथ चर्चा के केंद्र में हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराज़गी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर राजनीतिक घमासान जारी है और कई राज्यों में चुनावी तैयारियां भी तेज़ हो रही हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद जनता की समस्याओं का समाधान खोजने का मंच बन रही है, या केवल राजनीतिक टकराव का अखाड़ा?लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से जवाब मांगने की होती है। यदि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप हैं या किसी सार्वजनिक संस्था के वित्तीय लेनदेन पर सवाल उठ रहे हैं, तो इन मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। वहीं सरकार का दायित्व है कि वह तथ्यों के आधार पर जवाब दे और यदि आवश्यक हो तो जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। लेकिन जब सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की वजह से बाधित होती है, तब सबसे अधिक नुकसान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का होता है।संसद केवल आरोप और प्रत्यारोप का मंच नहीं है। यहीं कानून बनते हैं, आर्थिक नीतियां तय होती हैं और देश की दिशा निर्धारित होती है। हर दिन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपये का सार्वजनिक खर्च होता है। ऐसे में यदि प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे महत्वपूर्ण अवसर हंगामे की भेंट चढ़ जाएं, तो जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यह स्थिति सरकार और विपक्ष—दोनों के लिए आत्ममंथन का विषय है।दूसरी ओर, NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न हैं। इसी तरह, किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक ट्रस्ट पर यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो निष्पक्ष जांच होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है, लेकिन जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।आने वाले दिनों में संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है। ऐसे समय में देश की अपेक्षा यही है कि राजनीतिक दल केवल विरोध या समर्थन तक सीमित न रहें, बल्कि सार्थक बहस के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करें। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि मतभेदों को संवाद के जरिए कैसे सुलझाया जाता है, न कि केवल नारों और व्यवधानों से।

निष्कर्ष:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को बहस करने, जवाब मांगने और कानून बनाने के लिए चुना है, न कि केवल टकराव के लिए। यदि संसद में संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता मिले, तभी लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

NEET और राम मंदिर ट्रस्ट मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा पहले ही दिन दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और यह 13 अगस्त तक चलेगा।सत्र के पहले ही दिन NEET-UG 2026 पेपर लीक और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए दोनों सदनों में हंगामा किया।लगातार विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले ही दिन स्थगित करनी पड़ी, जिससे सत्र की शुरुआत राजनीतिक टकराव के साथ हुई।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को जोरदार राजनीतिक टकराव के साथ हुई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने NEET-UG 2026 पेपर लीक और अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित डोनेशन गड़बड़ी के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी। लगातार व्यवधान के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का यह मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ-साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है।हंगामे के बीच सरकार ने अपना विधायी कामकाज जारी रखने की कोशिश की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया। इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण में मदद मिलेगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। यह विधेयक पहले जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।विपक्ष के हंगामे का असर संसद की नियमित कार्यवाही पर भी पड़ा। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके, जिससे सांसदों को जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिल पाया। दूसरी ओर, राज्यसभा में सरकार 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का अपमान करने या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाएगा।इसी दौरान राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने विभिन्न राज्यों से निर्वाचित नौ नए सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें गुजरात से भाजपा के मुकेशभाई जे. राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवट, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पांगसांग कोंगकल संगमा, मिजोरम से खियांग्टे लालत्लुआंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के सतीश पूनिया तथा पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चिक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय शामिल हैं।विपक्ष ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह पूरे मानसून सत्र के दौरान NEET-UG 2026 पेपर लीक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा। वहीं सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने और अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 13 अगस्त तक चलने वाला यह मानसून सत्र राजनीतिक रूप से बेहद गरम रहने वाला है और सदन के भीतर तीखी बहस तथा टकराव देखने को मिल सकते हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखा हमला बोला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्काईरूट के 28 वर्षीय युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनकी दुनिया सराहना कर रही है, लेकिन NEET-UG पेपर लीक से प्रभावित उन छात्रों का जिक्र नहीं किया, जिनके भविष्य पर संकट आया।' प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग के बावजूद सरकार लगातार बचा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के ऐसे 'खास रत्न' बन गए हैं, जिन्हें हर हाल में संरक्षण दिया जा रहा है। NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। इसी मुद्दे पर संसद सत्र की शुरुआत के साथ राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक मामले का विषय उठाया। खरगे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। खरगे ने पेपर लीक और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि देशभर के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उधर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके तुरंत बाद विपक्षी बेंचों से नारेबाजी हुई, जिसके साथ सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने शांति बनाए रखने की अपील दोहराते हुए कहा, 'संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और सभी को बोलने का समय दिया जाएगा।'स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके कुछ ही देर बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी थी। लेकिन विपक्षी दलों के विरोध को देखते हुए पूरे दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

मंत्री रामकृपाल यादव ने जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर भाजपा की ताकत देखकर घबरा गए हैं और उन्हें बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। रामकृपाल यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर देश-विदेश घूमते रहे हैं। उन्हें बांकीपुर विधानसभा की चौहद्दी तक नहीं पता। जिसे अपने चुनाव क्षेत्र की चौहद्दी का ही पता नहीं है, वह चुनाव क्या जीतेगा?" उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा, "2025 का चुनाव परिणाम बताता है कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे भाजपा की ताकत देखकर घबरा गए हैं।" भाजपा के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी का संगठन और नेतृत्व दोनों बेहद मजबूत हैं। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि विपक्षी दल और उनके नेता उससे भयभीत हैं। यही वजह है कि वे लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं।" बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा और जन सुराज के बीच जुबानी हमले भी लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसे में यह उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। इधर, जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि लोग भाजपा के सांसदों और विधायकों को अपने बीच सक्रिय देखना चाहते हैं, तो उन्हें इस उपचुनाव में भाजपा को हराना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, "अभी आपने अपनी ताकत का सिर्फ एक प्रतिशत दिखाया है, इसलिए भाजपा के नेता आपके दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। जिस दिन आप अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे, उस दिन वे आपकी हर बात मानेंगे और आपका हर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "आज 40-50 मंत्री और विधायक गली-गली घूम रहे हैं। यह मेरी ताकत नहीं, बल्कि बांकीपुर की जनता की ताकत है। मेरे पास न कोई बड़ा संगठन है और न ही कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। मेरे साथ सिर्फ जनता खड़ी है। जनता ही कह रही है कि इस बार बांकीपुर में बदलाव होकर रहेगा।"

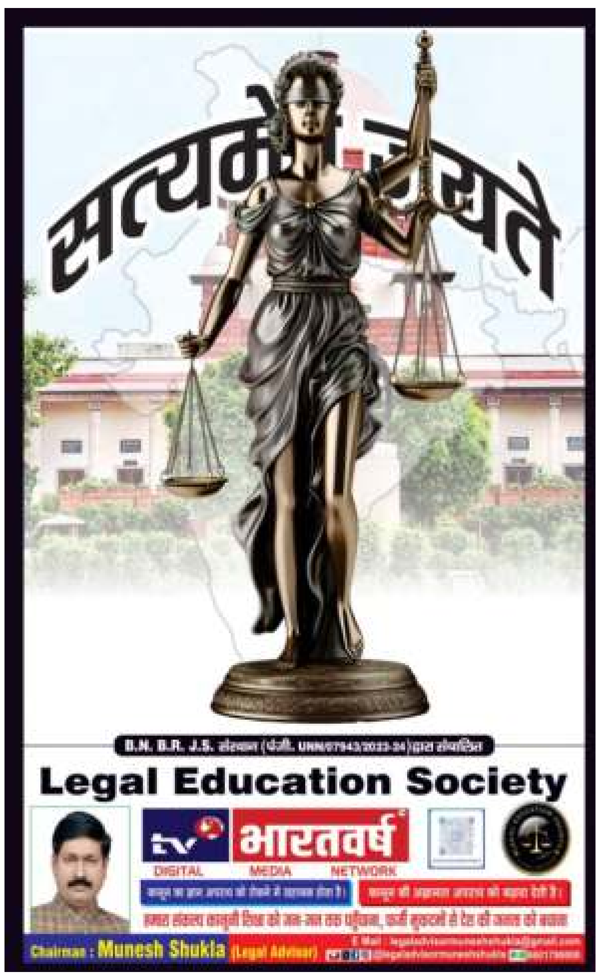

बिहार में टीचर्स ट्रांसफर का नया सिस्टम

बीमारी, अनुभव और दिव्यांगता को मिलेगा वेटेज

बिहार के 5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर का तोड़ निकाल लिया है। बिहार शिक्षा विभाग इसके लिए एक मार्किंग सिस्टम आई है, जिसमें 100 नंबर तय करेंगे कि टीचर्स का ट्रांसफर कब और कैसे होगा। शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए 100 अंकों वाली एक नई एपीआई बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026' लागू की है। इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी, ऑनलाइन और मानवीय प्रथामिकताओं पर आधारित बनाना है। तबादले की इस नई नीति के 5 मुख्य नियम इस प्रकार हैं- ट्रांसफर के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। टीचर्स पोर्टल के जरिए अपनी वरीयता जैसे मनपसंद स्कूल का ऑप्शन भरकर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को 100 नंबर की API के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। गंभीर बीमारी वाले टीचर्स को सीधे 20 नंबर दिए जाएंगे। निर्धारित मानक वाले दिव्यांग शिक्षकों को 15 नंबर, महिला शिक्षकों और ऐसे शिक्षक पति-पत्नी जो एक-दूसरे से दूर स्कूल में तैनात हैं, उन्हें 10-10 नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 31 मार्च तक की सेवा अवधि के आधार पर हर साल के लिए अंक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान तैनाती के भी नंबर मिलेंगे।महिला शिक्षकों को उनके गृह पंचायत को छोड़कर उसी ब्लॉक की किसी नजदीकी पंचायत में ट्रांसफर दिया जा सकता है। वहीं पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड को छोड़ उसी जिले के किसी नजदीकी दूसरे प्रखंड में ट्रांसफर दिया जाएगा।तबादले की पूरी प्रक्रिया स्कूलों में खाली पड़े पदों और वहां शिक्षकों की जरूरत के आधार होगी। मेरिट और सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बने रहे। vबिहार शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी और पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर पूरी होने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई 2026 से खुल जाएगा। टीचर्स 5 अगस्त तक लॉगिन करके ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट फाइल कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देशों के बाद विभाग ने इस टाइम टेबल को अंतिम रूप दिया है जिससे भ्रष्टाचार और पैरवी संस्कृति पर पूरी तरह से रोक लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

बिहार संग्रहालय में पेड इंटर्नशिप का मौका, युवाओं को मिलेगा ₹6,000 तक स्टाइपेंड

करियर के शुरुआती फेज में अच्छी जगह इंटर्नशिप करना भविष्य में आपके लिए अच्छी संभावनाएं ला सकता है। जो कैंडिडेट्स ऐसी ही इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो बिहार संग्रहालय पटना में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजियम ने सोशल मीडिया असिस्टेंट और डेटा मैनेजमेंट/एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए इंटर्नशिप निकाली है। चयनित कैंडिडेट्स को हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। बिहार संग्रहालय राज्य के सबसे प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शामिल हैं। यहां काम करना उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अवसर हो सकता है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को करीब से जानना समझना चाहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया असिस्टेंट और डेटा मैनेजमेंट के काम का यह अनुभव आपके सीवी को तो मजबूत बनाएगा ही, साथ में आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। इस इंटर्नशिप के लिए बिहार कौशल मिशन ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। vबिहार संग्रहालय में सोशल मीडिया असिस्टेंट की पोस्ट पर इंटर्नशिप करने के लिए उम्मीदवारों का फाइन आर्ट्स, बीएफए, एमएफए में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए करने वाले अभ्यर्थी डेटा मैनेजमेंट और एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोनों पदों पर काम करने की तरीका और जिम्मेदारी अलग-अलग है, इसीलिए शैक्षिक योग्यता भी पोस्ट वाइज अलग-अलग रखी गई है। ग्रेजुशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स को 6000 रुपये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं गृह जिला से बाहर कार्यस्थल होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 2000 रुपये अतिरिक्त से भी दिए जाएंगे।

अर्जेंटीना खिलाड़ियों की खेल भावना पर सवाल स्पेन के ट्रॉफी समारोह का किया बहिष्कार

पीवी सिंधू चीन ओपन में भारतीय दल की कमान संभालेंगी

ओपन का खिताब जीतकर शानदार लय में लौटी भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधू मंगलवार से शुरु हो रहे चीन ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी लेकिन पुरुष युगल की शीर्ष जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कंधे की चोट से उबर रहे सात्विक के कारण इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय टीम बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर पर पिछले सप्ताह के शानदार प्रदर्शन की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। सिंधू लगभग दो वर्ष बाद जापान ओपन का खिताब जीतकर बेहतरीन लय में चीन पहुंची हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने जापान ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में तीन बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को हराया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले सीधे गेमों में जीतकर खिताब अपने नाम किया। सिंधू अपने अभियान की शुरुआत हमवतन उन्नति हुड्डा के खिलाफ करेंगी। दूसरे दौर में उनका सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चेन यू फेई से हो सकता है। महिला एकल में भारत की अन्य खिलाड़ी देविका सिहाग अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान के खिलाफ करेंगी। पिछले महीने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब जीतने वाले सात्विक और चिराग ने जापान ओपन से भी सात्विक की बार-बार उभर रही कंधे की चोट के कारण नाम वापस ले लिया था। अब दोनों ने विश्व चैंपियनशिप से पहले पूरी तरह फिट होने के उद्देश्य से चीन ओपन नहीं खेलने का फैसला किया है। विश्व चैंपियनशिप 17 वर्ष बाद भारत में आयोजित होने जा रही है। पुरुष एकल में भारत की चुनौती का जिम्मा पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन, विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज आयुष शेट्टी और अनुभवी एचएस प्रणय संभालेंगे। लक्ष्य सेन शुरुआती दौर में जापान के युशी तनाका से भिड़ेंगे।

टूट गया ब्राजील के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी का सपना

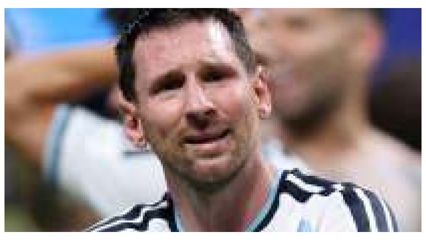

मेटलाइफ स्टेडियम में मौजूद 80 हजार से अधिक दर्शकों और दुनिया के कोने-कोने में देर रात तक टीवी स्क्रीनों के सामने नजरें गड़ाए बैठे करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की जुबां पर सिर्फ एक ही नाम था–लियोनेल मेस्सी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विश्व कप के अपने सुनहरे सफर के आखिरी पड़ाव पर दुनिया का यह सबसे चमकता सितारा बेनूर हो गया। अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में फेरान टोरेस द्वारा दागे गए गोल के दम पर स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व फुटबॉल की बादशाहत दक्षिण अमेरिकी धुरंधर से छीन ली।अर्जेंटीना की टीम महान पेले के दौर के ब्राजील (1958 और 1962) के बाद लगातार दो बार विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बनने का सपना लेकर मैदान पर उतरी थी। लेकिन स्पेन के अभेद्य रक्षण के आगे मेस्सी का यह ऐतिहासिक सपना टूट गया। मैच की आखिरी सीटी बजते ही जहां एक तरफ स्पेनिश खेमा जश्न में डूब गया, वहीं दूसरी तरफ मेस्सी की आंखों में नमी और चेहरे पर छाई गहरी निराशा को पूरी दुनिया ने देखा। पराजय के बाद मेस्सी और उनकी टीम ने स्टेडियम के दक्षिणी छोर पर खड़े अर्जेंटीना के प्रशंसकों का आभार जताया और इस हार के लिए मूक माफी भी मांगी। एक तरफ स्पेन के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ मेस्सी और उनकी टीम स्टेडियम के दक्षिणी छोर पर अर्जेंटीना के समर्थकों को धन्यवाद दे रही थी और शायद माफी भी मांग रही थी। अर्जेंटीना को फ्रांस के खिलाफ 2022 विश्व कप में खिताबी जीत और दो बार कोपा अमेरिका खिताब दिलाने में सूत्रधार रहे मेस्सी स्पेन का गोल होने के बाद सिर झुकाये और कमर पर हाथ रखकर स्तब्ध खड़े रहे।

लगातार दो विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी- एम्बाप्पे

किलियन एम्बाप्पे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक आक्रमणकारी खिलाड़ियों में से एक हैं। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप में लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीतकर नया इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी गोल करने में सफल नहीं रहे, जिसके बाद एम्बाप्पे 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने रहे।किलियन एम्बाप्पे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक आक्रमणकारी खिलाड़ियों में से एक हैं। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी ने पुरुष फुटबॉल विश्व कप में लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीतकर नया इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी गोल करने में सफल नहीं रहे, जिसके बाद एम्बाप्पे 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने रहे। बता दें कि एम्बाप्पे ने तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दो गोल किए। हालांकि फ्रांस को 6-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन दो गोलों की बदौलत उनका कुल गोलों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने लगातार दूसरी बार विश्व कप का गोल्डन बूट अपने नाम किया। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2022 के विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया था। गौरतलब है कि लगातार दो विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार इस बार गोल्डन बूट की दौड़ काफी रोमांचक रही। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी आठ गोल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नॉर्वे के एरलिंग हालांड और इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम ने सात-सात गोल किए। इंग्लैंड के हैरी केन और फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने छह-छह गोल कर प्रतियोगिता का समापन किया। एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट की शुरुआत भी शानदार अंदाज में की

थी। उन्होंने सेनेगल के खिलाफ पहले मुकाबले में दो गोल किए। इसके बाद इराक के खिलाफ भी दो बार गेंद को जाल में पहुंचाया। नॉर्वे के खिलाफ वह गोल नहीं कर सके, लेकिन स्वीडन के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में फिर दो गोल दागकर अपनी शानदार लय बरकरार रखी। इसके बाद पराग्वे के खिलाफ उनका पेनाल्टी से किया गया गोल फ्रांस की जीत का कारण बना। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ भी उन्होंने एक गोल किया।

दिल्ली के कैब ड्राइवर की भावुक कहानी

80 लाख के 2 फ्लैट, फिर भी ऊबर क्यों चलाता है शख्स?

महीने में 80 हजार रुपये किराया आए और करीब 80 लाख रुपये के दो फ्लैट हों, तो शायद ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी चुनना पसंद करेंगे. लेकिन दिल्ली के एक उबर ड्राइवर की कहानी कुछ अलग है. दावा है कि दो फ्लैट से अच्छी-खासी कमाई होने के बावजूद वह रोजाना करीब 12 घंटे कैब चलाता है और महीने के लगभग 50 हजार रुपये अलग से कमाता है. इसके पीछे की वजह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी घटना है, जिसने उसे खुद को साबित करने के लिए प्रेरित किया. दिल्ली के इस उबर ड्राइवर की कहानी आस्था सेठ नाम की एक महिला ने इंस्टाग्राम

पर शेयर की है. उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि कैब राइड के दौरान उनकी ड्राइवर से करीब पांच मिनट बातचीत हुई. इस छोटी सी बातचीत में ड्राइवर ने अपनी जिंदगी के बारे में जो बताया, उसने उन्हें काफी प्रभावित किया. आस्था सेठ के मुताबिक, ड्राइवर मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है.

जापान में शुरू हुआ 'हॉन्टेड हाउस सिटर' का अनोखा पेशा

डरावने घर में एक रात बिताने के ₹52 हजार

क्या आप किसी ऐसे घर में पूरी रात अकेले रह सकते हैं, जहां किसी की हत्या हुई हो या जिसे लेकर भूतिया होने की अफवाह हो? शायद ज्यादातर लोग ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे. लेकिन जापान में अब ऐसे कथित 'भूतिया घरों' में रात बिताना बाकायदा एक पेशा बनता जा रहा है. यहां लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी में एक रात बिताने के लिए 88,000 येन यानी करीब 52 हजार रुपये तक दिए जा रहे हैं. इस काम के पीछे मकसद भूतों की तलाश करना भर नहीं, बल्कि खाली पड़े मकानों को दोबारा बेचने या किराए पर देने में मदद करना है. ये लोग रातभर घर में रहकर कैमरों और दूसरे उपकरणों की मदद से कथित पैरानॉर्मल एक्टिविटी की

जांच करते हैं. अगर रातभर कुछ असामान्य नहीं होता, तो प्रॉपर्टी को लेकर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि वहां कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली.

द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जापान में ऐसी प्रॉपर्टी को 'जिक्को बुक्केन' कहा जाता है, जहां किसी व्यक्ति की मौत असामान्य या परेशान करने वाली परिस्थितियों में हुई हो. इनमें हत्या, आत्महत्या, जानलेवा आग या 'लोनली डेथ' जैसे मामले शामिल हो सकते हैं. 'लोनली डेथ' उन मामलों को कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति अकेले घर में मर जाता है और उसकी मौत का कई दिनों या हफ्तों तक पता नहीं चलता.

ही एक ठगी का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कैंसर पीड़ित बनकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली मिस्र की

उन्हें कभी कैंसर था ही नहीं.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनिया फौद सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर करती थीं, जिनमें वह खुद को

महंगी लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे. डोनिया फौद डोनेशन में मिले पैसों से उन्होंने कार खरीदी, फ्लैट लिया और कई लग्जरी

रिपोर्ट में न कीमोथेरेपी का जिक्र था और न ही रेडिएशन का. बताया गया कि डोनिया को सिर्फ कुछ सामान्य स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें थीं, जिनका इलाज चल रहा था.

अनुमानित और व्यवस्थित, लेकिन कुछ कमी लगती थी भारत में ट्रैफिक है, प्रदूषण है, शोर है, भीड़ है, अनिश्चितता है... फिर भी यहां कुछ है जो वहां नहीं मिलता.

अमेरिका में हरी मिर्च खरीदना हुआ सोना-चांदी खरीदने जैसा

भारत में किसी सब्जीमंडी जाएं, आलू, प्याज, परवर साथ लें और जब सब्जीवाला ये सब सामान पैक कर रहा है तो उससे आप कह देते हैं कि भाई थोड़ा सा मिर्चा भी डाल दें. और वो डाल भी देता है. और इसकी कीमत भी नहीं लेता. ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इससे अंदाजा लग जाए भारत में मिर्च की कितनी इफराती है. लेकिन अमेरिका में इसी मिर्ची की कीमत जानकर लोग हैरान हैं. वीडियो में वो कहती हैं कि अमेरिका में मिर्ची खरीदना सोना-चांदी खरीदने जैसा है.

जोरदार किक से धड़ से अलग हुआ सिर, फिर भी लड़ता रहा ह्यूमनॉइड

चीन में रोबोट्स की तगड़ी जंग!

चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच हुई फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है. मुकाबले के दौरान जोरदार किक लगने से एक रोबोट का सिर लटक गया और बाद में अलग हो गया. हैरानी की बात यह रही कि सिर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद रोबोट ने फाइट जारी रखने की कोशिश की.

रोबोट्स की दुनिया तेजी से बदल रही है. कभी ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों की तरह दौड़ते और डांस करते दिखाई देते हैं, तो कभी फैक्ट्री में काम करते नजर आते हैं. रोबोट का ऐसा ही एक हैरान करने वाला कारनामा चीन से सामने आया है. वीडियो में दो ह्यूमनॉइड रोबोट किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक-दूसरे पर पंच और किक बरसाते दिख रहे हैं. मुकाबला इतना जबरदस्त था कि एक रोबोट का सिर तक अलग हो गया. हैरानी की बात यह रही कि सिर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद रोबोट ने फाइट जारी रखने की कोशिश की.

न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना चीन के शेनझेन में दुनिया के पहले फुल-साइज ह्यूमनॉइड रोबोट फ्री-कॉम्बेट टूर्नामेंट के दौरान हुई. अल्टीमेट रोबोट नॉक-आउट लीजेंड (URKL) नाम के इस टूर्नामेंट में रोबोट्स के बीच मुकाबला कराया गया. इस फाइट का वीडियो अब वायरल हो रहा है. मुकाबला व्हाइट ईगल और मेटाडोर नाम के दो T800 ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच था. फाइट के दौरान दोनों रोबोट एक-दूसरे पर पंच और किक से हमला करते नजर आए. इसी बीच व्हाइट ईगल ने मेटाडोर को एक जोरदार हाई किक मारी.

क्या है T800 ह्यूमनॉइड रोबोट?

T800 एक फुल-साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है. इसे चीन की रोबोटिक्स कंपनी EngineAI ने विकसित किया है. कंपनी इससे पहले भी T800 को कई तरह के मार्शल आर्ट्स से प्रेरित मूव्स करते हुए दिखा चुकी है. इनमें पंच कॉम्बिनेशन, राउंडहाउस किक और किक-पंच कॉम्बिनेशन जैसे मूव्स शामिल हैं.

सलमान के चेहरे से उड़ी रौनक, चिंता में डूबे सुपरस्टार के फैंस

सलमान खान अपने नए लुक को लेकर कुछ समय पहले सुर्खियों में आए थे. बीते दिन वो मुंबई में एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के ऑफिस में पहुंचे, जहां उन्होंने आईटी सर्विस रूम का उद्घाटन किया. इस मीटिंग की कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं. SRA ऑफिस में सलमान की मौजूदगी कई लोगों

की नजरों में आई. हालांकि इस मीटिंग से ज्यादा उनके लुक की चर्चा हुई.

एआर रहमान और हान्स जिमर के म्यूजिक ने बांधा समां

शानदार विजुअल्स से सजा 'रामायण' का ट्रेलर

भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राज्य, धर्म और समाज से आता हो... रामायण की कहानी पता है. इसलिए प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' पर लोगों की नजरें पहली अनाउंसमेंट के समय से ही लगी हैं. 'रामायण' का टीजर आया तो एक्साइटमेंट के साथ-साथ कुछ सवाल भी बढ़े. विजुअल्स से लोगों को कुछ ऐसी शिकायतें हुईं जो 4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म से नहीं होनी चाहिए. इसलिए ट्रेलर का इंतजार और तगड़ा हो गया. शनिवार, 18 जुलाई की शाम को, दिल्ली में 'रामायण' का पहला ट्रेलर रिवील हुआ, जो दुनिया के सामने कुछ दिन बाद आएगा. हमें भी ट्रेलर देखने का मौका मिला. और ये ट्रेलर देखने के बाद कहा जा सकता है कि 'रामायण' पर उठ रहे सवाल कपूर की तरह उड़ जाएंगे, बचेगा तो सिर्फ दीवाली पर फ़िल्म रिलीज होने का उत्साह. भारत मंडपम में जिस स्क्रीन पर 'रामायण' का ट्रेलर दिखाया गया, वो प्रॉपर सिनेमा सेटअप नहीं है. लेकिन 3डी ट्रेलर की क्वालिटी बता रही थी कि एक शानदार सिनेमा स्क्रेवन पर ये कितना बेहतरीन लगेगा.

NEET पेपर लीक पर विपक्ष का प्रदर्शन, डिंपल यादव समेत कई सपा सांसद हिरासत में

NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विपक्ष ने सोमवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद से जंतर-मंतर तक मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई देखने को मिली।

नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि संसद से जंतर-मंतर तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान डिंपल यादव समेत पार्टी के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। सपा ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, अक्षय यादव, आदित्य यादव, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, हरेंद्र मलिक और इकरा हसन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने में बैठाया। पार्टी का कहना है कि सभी CJP के समर्थन में संसद से जंतर-मंतर तक पैदल मार्च कर रहे थे। सपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छात्रों की आवाज उठा रहे सांसदों को हिरासत में लेना और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के आंखों में भी शर्मिंदगी दिख रही थी, कुछ पुलिसकर्मी गुंडे बने हुए थे, कुछ पुलिसवाले बिना वर्दी के आए और बच्चों को मारा है। जबकि नियम होता है कि आपको पैरों पर मारना है वहां बच्चों के सीने पर मारा है। उन्होंने कहा, 'ये हमला भारत माता के सीने पर किया है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाएं, सरकार जिम्मेदारी ले, इतनी अहंकारी कठोर और निर्दयी सरकार शायद ही देश के इतिहास ने देखी हो।' संसद परिसर के बाहर अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि बाहर छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। यह कैसी सरकार है, आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते। अखिलेश यादव यह सरकार नहीं, अहंकार है। करोड़ों युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनना ही नहीं चाहती। दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद कई कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाकर बसों में बैठाया और ईको गार्डन ले गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में किताबें थीं, जिनके ऊपर जंजीर से बंधा बुलडोजर का प्रतीकात्मक मॉडल रखा गया था। वाराणसी में समाजवादी छात्र सभा और बीएचयू से जुड़े कई छात्र नेताओं को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। नरिया चौराहा, लंका और काशी विद्यापीठ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

नशे की हालत में नहर में गिरे व्यक्ति को बचाया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

पारा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक व्यक्ति नशे की हालत में थाने के सामने स्थित नहर में गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में से एक सिपाही रस्सी लेकर उसे बचाने कूद गया। सिपाही ने 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद दूसरे सिपाहियों ने उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। इस बचाव अभियान में एक पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल भी हो गया। जानकारी के अनुसार, देर रात एक युवक नहर के पास पहुंचा और नशे की हालत में अचानक नहर में गिर। युवक को नहर में गिरते देख आसपास मौजूद लोग चिल्लाने लगे। सूचना मिलते ही पारा थाने पर तैनात आरक्षी उदय भान और मनोज तुरंत मौके पर पहुंचे। उसी समय जोनल चेकिंग कर रहे उप निरीक्षक रविशंकर मौर्य और पुलिसकर्मी राजेश गुप्ता भी वहां पहुंच गए। पुलिस टीम ने बिना देरी किए बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद युवक को नहर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान कॉन्स्टेबल मनोज को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उनकी हालत सामान्य बताई गई है। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान शिव शंकर पुत्र दुलारे, निवासी डूडा कॉलोनी, हंसखेड़ा, थाना पारा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, वह शराब के नशे में था। उसे समझाने-बुझाने के बाद सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और घटना की पूरी जानकारी दी गई। पारा पुलिस की इस त्वरित और मानवीय कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते सक्रियता नहीं दिखाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस अधिकारियों ने भी बचाव अभियान में शामिल जवानों की प्रशंसा की है।

लखनऊ विश्वविद्यालय LLM प्रवेश परीक्षा में नकल का आरोप, मोबाइल के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी खिड़की तोड़कर फरार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकेंड कैंपस में सोमवार को LLM प्रवेश परीक्षा के दौरान 2 बजे जमकर हंगामा हो गया। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर नकल को लेकर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान एडमिशन सेल के कर्मचारियों और मौजूद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के साथ अभ्यर्थियों की बहस हो गई। देखते ही देखते बहस के साथ धक्का-मुक्की भी होने लगी। माहौल बिगड़ गया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा कक्ष में कुछ लोग मोबाइल फोन लेकर परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में नकलविहीन परीक्षा कैसे कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। इसी बीच मोबाइल फोन से नकल करते पकड़ा गया एक अभ्यर्थी पूछताछ के दौरान कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के सेकेंड कैंपस में सोमवार को LLM प्रवेश परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने के बाद एक अभ्यर्थी पूछताछ से बचने के लिए कमरे की खिड़की तोड़कर परीक्षा केंद्र से भाग गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भेजा है। घटना सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित इंजीनियरिंग फैकल्टी

परीक्षा केंद्र पर आयोजित LLM प्रवेश परीक्षा की पहली पाली के दौरान हुई। विश्वविद्यालय के अनुसार, परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 336 में परीक्षा दे रहे अलीगढ़ निवासी जतिन वार्ष्णेय को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए केंद्र अधीक्षक प्रो. आनंद कुमार विश्वकर्मा और आंतरिक उड़नदस्ते ने पकड़ा। विश्वविद्यालय के मुताबिक, पकड़े जाने के बाद अभ्यर्थी को अनुशासनात्मक कार्रवाई और पूछताछ के लिए इंजीनियरिंग फैकल्टी के प्रथम तल पर स्थित एक कमरे में ले जाया गया। सुरक्षा के लिए कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था। आरोप है कि कुछ देर बाद अभ्यर्थी ने कमरे के पीछे की खिड़की तोड़ दी और परीक्षा केंद्र से फरार हो गया।

लखनऊ सहित छह जिलों में लोगों को मिलेंगे सस्ते आवास

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी में सीतापुर रोड पर नैमिष नगर, आगरा एक्सप्रेसवे के करीब वरुण विहार, सुलतानपुर रोड किसान पथ के पास आइटी सिटी व वेलनेस सिटी आवासीय योजनाएं ही आकार नहीं लेंगी, बल्कि हर परिवार के पास आवास होने का भी प्रबंध हो रहा है। राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में दांचागत विकास के तहत लखनऊ के अलावा एससीआर में शामिल बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई व रायबरेली में 48.75 लाख आवास बनेंगे। आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर 13.36 लाख अफोर्डेबल यानी सस्ते आवास भी होंगे। इनमें 33 लाख 40 हजार लोग रह सकेंगे। एससीआर बनने पर राजधानी व आसपास का क्षेत्र रोजगार का भी केंद्र होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में आकर रहेंगे। उनके लिए किफायती हाउसिंग टाउनशिप बनेगी, जिसमें गरीबों व आम लोगों के लिए क्रमशः ईडब्ल्यूएस और एलआइजी घर बनाए जाएंगे। एससीआर की बीती दस जुलाई को विभिन्न विभागों की बैठक में कहा गया, 2051 तक 48.75 आवासों की जरूरत होने का अनुमान है। इनमें 13.36 लाख आवास सस्ते आवास होंगे। उसी को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं का खाका अभी से खींचा जा रहा।

'नगर निगम अफसरों की लापरवाही से गई लालाराम की जान'

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में अंडरग्राउंड नाले की सफाई के दौरान हुई कर्मचारी की मौत के मामले में नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सफाई कर्मियों का आरोप है कि नालों की सफाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। सिर्फ कागजों में गुणवत्तापरख काम कर रहे हैं। ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। नालों की सफाई के दौरान नगर निगम की तरफ सुरक्षा मानकों को लेकर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। सबकुछ ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लालाराम को भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अंडरग्राउंड नाले में उतारा गया था। उसकी मौत के बाद भी शहर में बिना सुरक्षा उपकरण के नालों की सफाई कराई जा रही है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार, मैनहोल या सीवर की सफाई से पहले मानक प्रक्रिया के तहत परीक्षण टेस्टिंग की तैयारी के लिए कम से कम तीन मैनहोल के ढक्कन खोले जाते हैं। इसके बाद लाइन में ताजी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक सक्शन पंप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लाइन के अंदर प्रवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके ऑक्सीजन की रीडिंग ली जाती है। इसके साथ ही यातायात में व्यवधान कम हो इस लिए रात में काम को करने की सलाह है। हालांकि, यह काम व्यस्त चौराहे पर दोपहर के समय में किया गया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में बताए गए करीब सभी नियमों का चिनहट तिराहे पर नाला सफाई के दौरान उल्लंघन किया गया। बावजूद इसके अधिकारी सिर्फ कांट्रैक्ट नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।

लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग, सरकारी दफ्तरों में मची अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के प्रमुख केंद्र जवाहर भवन में सोमवार को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और दूर तक उठता धुएं का गुबार देखकर भवन में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया।सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया। पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य लगातार जारी था और पूरे परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक जवाहर भवन के एक हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते धुआं घना हो गया और कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं। भवन में मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलना शुरू कर दिया। आग फैलने की आशंका के चलते पूरे परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को व्यवस्थित

तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया और भवन को खाली कराया। आग की सूचना मिलते ही आसपास के कार्यालयों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल फायर कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव दल तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने ऊंची सीढ़ियों, हाई-प्रेशर वाटर जेट और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। भवन के भीतर धुएं की अधिकता के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहले आग को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह भवन के अन्य हिस्सों तक न पहुंचे। इसके बाद अंदर मौजूद संभावित लोगों की तलाश और सुरक्षित निकासी का अभियान चलाया गया। दमकल कर्मी लगातार जोखिम उठाकर आग बुझाने में जुटे रहे।

उन्नाव में जलभराव पर नगर पालिका का घेराव, वार्ड-15 के लोगों ने किया प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बारिश के बाद शहर और कस्बों में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। सोमवार दोपहर को नगर पालिका परिषद उन्नाव के वार्ड-15, पहली खेड़ा के दर्जनों निवासी गंदगी और जलभराव की शिकायत लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की और तत्काल समाधान की मांग की। इसी बीच, बांगरमऊ स्थित ग्राम न्यायालय परिसर में भी जलभराव से अधिवक्ताओं और वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड-15 के निवासियों का आरोप है कि मोहल्ले में लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है। इसके चलते बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया है। जगह-जगह फैली गंदगी से दुर्गंध आ रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण कराया जाएगा और जल निकासी, नालियों की सफाई तथा गंदगी हटाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ईओ ने लोगों से इस कार्य में सहयोग की अपील भी की। उधर, बांगरमऊ के ग्राम न्यायालय परिसर में जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है। परिसर के कई हिस्सों में पानी जमा होने के कारण अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे फिसलकर चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि बरसात के मौसम में हर साल ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन अब तक जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कहना है कि न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण परिसर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है। जलभराव के कारण न्यायिक कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उन्नाव में नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला समेत छह घायल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के मौरावां थाना क्षेत्र के ग्राम पारा में सोमवार देर शाम नाली निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत छह लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात करीब 11 बजे उनका इलाज शुरू हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती घायल सईद अहमद ने बताया कि विवाद नाली निर्माण को लेकर शुरू हुआ था। उनका आरोप है कि गांव के असद, साना, अशरी, आसरा और चिट्टो सहित अन्य लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सईद अहमद के अलावा सलीम, रेहाना और मोइनुद्दीन समेत अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां काफी भीड़ जुट गई। चिकित्सकों की निगरानी में सभी घायलों का उपचार जारी है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

20 घंटे बिजली गुल रहने पर उन्नाव में लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव शहर की आवास विकास कॉलोनी में लगभग 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से सोमवार रात को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज मोहल्लेवासियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समाजसेवी गोपाल अवस्थी ने बताया कि रविवार रात से ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित थी। लगातार शिकायतें करने के बावजूद बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और उमस के बीच पूरी रात बिजली न रहने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार रात करीब दस बजे आवास विकास कॉलोनी क्रॉसिंग के पास रस्तोगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बावजूद विभाग की ओर से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही उपभोक्ताओं को समस्या के समाधान के संबंध में कोई जानकारी दी गई। प्रदर्शन में राधेश्याम शर्मा, नवीन रस्तोगी, संजय मिश्रा, बुलाई सिंह, राम बाबू, विनोद मिश्रा, जन्मेजय यादव, किशन अवस्थी सहित कई स्थानीय निवासी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग, आप ने सौंपा ज्ञापन

आम आदमी पार्टी के जिला संगठन ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। यह ज्ञापन जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे शिक्षाविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने युवाओं से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक की घटनाओं और प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कदम उठाने की मांग की। पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं ने युवाओं में चिंता पैदा की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सोनम वांगचुक युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आप ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं थी और इन घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर युवाओं के हितों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की अपील की। उनकी मांगों में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करना शामिल था। जिलाध्यक्ष कुलदीप यादव ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और शिक्षा व रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।

उन्नाव में सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में पोनी रोड चौड़ीकरण परियोजना को लेकर पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान अब गति पकड़ रहा है। शनिवार को अभियान शुरू होने के बाद जहां कुछ स्थानों पर नापजोख को लेकर विरोध हुआ था, वहीं अब अधिकांश प्रभावित परिवारों ने नुकसान कम करने के लिए स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को कई लोगों ने अपने मकानों के चबूतरे, सीढ़ियां, छज्जे और अन्य निर्माण खुद तोड़ दिए। पीडब्ल्यूडी की टीम ने बिदानगर से पोनी रोड झंडा चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले निर्माणों पर निशान लगाए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने नापजोख पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया और कार्रवाई से पहले मुनादी कराने तथा एक दिन का समय देने की मांग की थी। स्थिति को देखते हुए गंगाघाट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद अभियान को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब सोमवार से प्रभावित लोगों ने स्वयं ही अपने निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं। श्रीनगर लोहिया स्कूल से लेकर पोनी रोड के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने चबूतरे, सीढ़ियां और मकानों के आगे निकले छज्जे तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण होना तय है, इसलिए यदि वे स्वयं अतिक्रमण हटाएंगे तो मकान को कम नुकसान पहुंचेगा। यदि जेसीबी से कार्रवाई होगी तो भवनों को अधिक क्षति होने की आशंका है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, जिन स्थानों पर निशान लगाए गए हैं, केवल वहीं तक का अतिक्रमण हटाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य सड़क को निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप विकसित करना है ताकि भविष्य में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिले। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर नवीन चंद्र ने बताया कि लोगों को सहयोग करने के लिए समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोबारा अभियान शुरू करेगा। यदि कहीं अतिक्रमण शेष रहता है तो उसे विभागीय कार्रवाई के तहत हटाया जाएगा।

गंगाघाट में पुलिस ने कराया बहू-बेटी सम्मेलन, परिवार में प्रेम और सौहार्द का दिया संदेश

उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र में पुलिस विभाग ने सोमवार को बहू-बेटी सम्मेलन एवं चौपाल का आयोजन किया। जाजमऊ चौकी अंतर्गत ग्राम रजवा खेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा परिवारों में आपसी प्रेम, विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा देना था। इसमें बड़ी संख्या में सास, बहू, ननद, भाभी, माताएं, बेटियां, छात्राएं और ग्रामीण उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर विनी सिंह के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान प्रभारी परिवार परामर्श समिति डॉ. आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार डॉ. मनीष सिंह सेंगर, चौकी प्रभारी विनोद सिंह, उपनिरीक्षक सुभाष और ग्राम प्रधान गोविंद निषाद सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। चौपाल के दौरान वक्ताओं ने परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हर परिवार में बहू को बेटी के समान सम्मान और स्नेह मिलना चाहिए, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्षेत्राधिकारी नगर विनी सिंह ने बहुओं से सास को मां का सम्मान देने और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं को 1090, 112 और 108 जैसी आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी और जरूरत पड़ने पर उनका तत्काल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ सलाहकार डॉ. मनीष सिंह सेंगर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि परिवार की खुशहाली आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान पर आधारित होती है। उन्होंने महिलाओं से घर-परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की अपील की। सम्मेलन का एक भावनात्मक क्षण तब आया जब सास-बहू, ननद-भाभी और मां-बेटी ने एक-दूसरे को माला पहनाई, मिठाई खिलाई और गले लगकर पारिवारिक एकता व समरसता का संदेश दिया। उपस्थित महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा पहली बार ऐसा सकारात्मक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे परिवारों में प्रेम और आपसी समझ बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने किया।

सीएम योगी ने लॉन्च किया 35 करोड़ पौधारोपण अभियान

'एक पेड़ मां के नाम' बना जनआंदोलन का संकल्प

मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति में प्रकृति के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में पृथ्वी को माता, नदियों को जीवनदायिनी और वृक्षों को जीवन का आधार माना गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वृक्षारोपण हमारे लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है।

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से शनिवार को महावृक्षारोपण अभियान-2026 की शुरुआत की गई। इस वर्ष राज्य सरकार ने एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान की थीम "एक पेड़ मां के नाम" रखी गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि से पौधारोपण कर इस राज्यव्यापी अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति की सेवा का एक पवित्र संकल्प है। उन्होंने कहा कि पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और संतुलित पर्यावरण का आधार बनते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया।सीएम योगी ने बताया कि इस महाअभियान में 26 सरकारी विभाग समन्वय के साथ भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत केवल पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर विकास वाटिकाओं की स्थापना, पवित्र त्रिवेणी पौधारोपण, मौलश्री जैसे पौधों का रोपण तथा किसानों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र वितरित करने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी योजना न बनाकर जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाना है।मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति में प्रकृति के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में पृथ्वी को माता, नदियों को जीवनदायिनी और वृक्षों को जीवन का आधार माना गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वृक्षारोपण हमारे लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने परिवार के नाम पर कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाएं।इससे पहले 11 जुलाई को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को इस महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि 35 करोड़ पौधों का लक्ष्य केवल संख्या नहीं, बल्कि हरित और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प है। वहीं, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। राज्य सरकार का मानना है कि यदि प्रत्येक नागरिक पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाए, तो यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा जनआंदोलन साबित हो सकता है।

योगी सरकार ने विभागों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रस्तावित विकास कार्यों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महाकुंभ से पहले श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और आयोजन पूरी तरह सुरक्षित एवं व्यवस्थित हो।समीक्षा के दौरान सड़क चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवर, घाटों के सौंदर्यीकरण, सीवर और पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन तथा अस्थायी आवास जैसी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।सरकार ने प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष योजना तैयार की है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए रेलवे, सड़क परिवहन, पुलिस और नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आधुनिक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग को धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, स्वच्छता अभियान और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है।

योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर दान विवाद पर सपा-कांग्रेस पर तीखा हमला बोला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राम मंदिर के लिए मिले दान में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि वक्फ संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर ज़मीन पर कब्जे के मामले पर विपक्ष क्यों चुप रहा। प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे दूसरे मुद्दों को नज़रअंदाज़ करते हुए चुनिंदा तौर पर हिंदू धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ़ दो ही मुद्दे बचे हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में उन्होंने भारत की सनातन आस्था पर हमला करने की कैसी शरारतपूर्ण कोशिशें की हैं। कांग्रेस दावा करती थी कि भगवान राम का कभी अस्तित्व ही नहीं था, या भगवान कृष्ण कभी हुए ही नहीं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी—जिन्होंने कभी अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन किया था और उस पर मगरमच्छ के आँसू बहाए थे—वे कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियाँ चलवाईं। उन्हें आस्था के बारे में बात करने का क्या हक़ है—वे लोग जो हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए तय फंड को कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने में खर्च कर देते थे? वे किस तरह की आस्था की बात कर रहे हैं?... यह देश अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जाल में नहीं फँसेगा।राम मंदिर से जुड़े दान और वित्तीय प्रबंधन के आरोपों को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि उस ज़मीन का क्या हुआ जिस पर वक़्फ़ ने कब्ज़ा कर लिया है? किसी खास नेता का नाम लिए बिना आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ पार्टियां मंदिर को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि करोड़ों भक्तों के लिए इसका बहुत महत्व है। ये टिप्पणियां राम मंदिर से जुड़े चंदे और वित्तीय लेन-देन के आरोपों को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आई हैं। इस मुद्दे ने विपक्षी दलों को भाजपा सरकार और मंदिर ट्रस्ट को निशाना बनाने का नया मौका दे दिया है

कानपुर में 4.98 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा

उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने राज्य में हुई एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश करते हुए करीब 4.98 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस मामले में लखनऊ से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह फर्जी निवेश योजनाओं और डिजिटल ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था।जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से संपर्क किया। शुरुआत में निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर विश्वास जीता गया और बाद में बड़ी रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई गई। जब पीड़ितों ने पैसा निकालने की कोशिश की तो उनसे टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर अतिरिक्त रकम भी वसूली गई।साइबर सेल को कई राज्यों से शिकायतें मिलने के बाद जांच शुरू की गई। बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच करते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में कई अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साइबर अपराधियों के नेटवर्क से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश योजना या सोशल मीडिया पर मिलने वाले मुनाफे के झांसे में न आएं और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें।